भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 64
दिनांक 24 जुलाई, 2025

असम में गैस रिसाव की घटना

†*64. श्री गौरव गोगोईः
श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम के शिवसागर जिले में ओएनजीसी रुद्रसागर तेल क्षेत्र में हाल ही में हुई गैस रिसाव की घटना की औपचारिक जाँच के आदेश दिए हैं, जिसके कारण सैकड़ों निवासियों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) रिसाव के कारणों तथा प्रभावित क्षेत्र में कार्यशील तेल एवं गैस कंपनियों की भूमिका के बारे में प्रारंभिक निष्कर्ष, यदि कोई हों, क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों, जिनमें विस्थापित हुए लोग या स्वास्थ्य संबंधी नुकसान झेलने वाले लोग भी शामिल हैं, के लिए कोई मुआवज़ा घोषित किया गया है या धनराशि संवितरित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आपदा राहत और दीर्घकालिक पुनर्वास संबंधी किए गए अन्य उपाय क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण एलपीजी सिलेंडर का उपयोग बंद करने वाले निवासियों की आशंकाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा तेल एवं गैस अवसंरचना वाले क्षेत्रों में कड़ी निगरानी, आपातकालीन तैयारी और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) बुनियादी ढांचे के पिछली बार किए गए उन्नयन और देशभर में ऐसी अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और निवासियों पर इस रिसाव के प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी कोई अध्ययन शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (छ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'असम में गैस रिसाव की घटना' के बारे में संसद सदस्य श्री गौरव गोगोई और श्री प्रद्युत बोरदोलोई द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 64 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (छ) दिनांक 12 जून 2025 को असम के शिवसागर जिले में अवस्थित रुद्रसागर तेल क्षेत्र में ओएनजीसी के कूप आरडीएस-147ए में गैस रिसाव की घटना की सूचना प्राप्त हुई। त्वरित प्रतिक्रिया के साथ स्थापित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन करते हुए ओएनजीसी ने इस घटना से निपटने के लिए अपनी विशेषज्ञ टीमों को सक्रिय किया। जिला प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय में और अन्तरराष्ट्रीय कूप नियंत्रण विशेषज्ञों के सहयोग से, तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और समयबद्ध प्रतिक्रिया दी गई। दिनांक 27 जून 2025 को कूप को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर लिया गया। घटना के सुव्यवस्थित संचालन, सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन और जमीनी स्तर पर निरंतर समन्वय ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी चोट, मृत्यु, आग या विषाक्त उत्सर्जन न हुआ हो - जो घटना की तैयारी के लिए मौजूद व्यवस्था की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।

अपने अधिदेश के अनुरूप, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने घटना की औपचारिक जाँच शुरू की। प्रारंभिक निष्कर्षों ने इस बात की पुष्टि की कि इस घटना से किसी को कोई चोट नहीं आई है, कोई मौत नहीं हुई है, आग या विषाक्त उत्सर्जन नहीं हुआ है। गैस विश्लेषण से पता चला कि गैर-विषाक्त मीथेन (97.5%) का उत्सर्जन हुआ, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड या तरल हाइड्रोकार्बन की कोई उपस्थिति नहीं थी। प्रतिक्रिया अवधि के दौरान असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबीए) और ओएनजीसी द्वारा वायु और ध्वनि स्तर सहित पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी की गई। सभी मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर थे। पेयजल या कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिक्खो नदी तटबंध, जिसका आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान अस्थायी रूप से उपयोग किया गया था, ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से बहाल कर दिया गया।

इसके साथ-साथ जिला प्रशासन ने एक निवारक उपाय के रूप में, आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दिया। लगभग 350 परिवारों (लगभग 1,500 व्यक्तियों) को अस्थायी रूप से नौ पूरी तरह से सुसज्जित राहत-शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य सरकार ने इन शिविरों में भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की। तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) के अन्तर्गत 357 प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक को 25,000 रुपए का वितरण किया गया।

ओएनजीसी ने आवश्यक वस्तुओं, भोजन और पेयजल की आपूर्ति, अपना चिकित्सा-दलों और डॉक्टरों की तैनाती, सचल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और एम्बुलेंस सेवाएँ प्रदान करके इन प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग किया। कम्पनी ने सम्बन्धित हितधारकों के साथ रसद का समन्वय भी किया और बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंधों की बहाली में योगदान दिया। कूप को सुरक्षित रूप से ढकने (कैप) के बाद, ओएनजीसी ने निवासियों को सुरक्षित घर लौटने की सलाह दी। तदनुसार सभी पुनर्स्थापित परिवार अपने घर लौट गए। एलपीजी और

बिजली को फिर से चालू कर दिया गया। स्थानीय अधिकारियों और ओएनजीसी कर्मियों ने आशंकाओं को दूर करने और पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए समुदायों के साथ सीधे संपर्क किया। गंध या शोर के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए 3,000 से अधिक सुरक्षा मास्क और इयरप्लग वितरित किए गए।

तत्काल प्रतिक्रिया और राहत के साथ-साथ, सरकार द्वारा तेल और गैस क्षेत्र में सार्वजनिक सुरक्षा और प्रचालन लचीलेपन के लिए एक व्यापक ढाँचे का क्रियान्वयन जारी है। इसमें ओआईएसडी द्वारा नियमित सुरक्षा-ऑडिट और निरीक्षण, कूप के निर्माण और आपातकालीन तैयारियों के लिए कठोर तकनीकी मानकों का अनुपालन, वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप सुरक्षा दिशानिर्देशों का आवधिक अद्यतन, और ऑन-ग्राउंड सिमुलेशन के साथ अनिवार्य आपदा प्रबंधन योजनाएँ शामिल हैं। असम जैसे उच्च-संवेदनशील प्रचालन क्षेत्रों में ये उपाय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

इन सुरक्षा उपायों के पूरक के रूप में, ओएनजीसी ने देश भर में अवसंरचना ढाँचे के आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। पिछले पाँच वर्षों में, 8,416 करोड़ रुपए के संचयी निवेश के साथ नौ प्रमुख परियोजनाएँ पूरी हुई हैं।

असम में प्रमुख परियोजनाएँ जो या तो पूरी हो चुकी हैं या प्रक्रियाधीन है, का विवरण निम्नानुसार है -

- पाइपलाइन नेटवर्क परियोजना (पीएनपी), गेलेकी - ₹277 करोड़ (पूरी हो चुकी हैं),
- रुद्रसागर और गेलेकी में नए फ्लेयर सिस्टम - 76 करोड़,
- लकवा में गैस कम्प्रेशन प्लांट (119 करोड़ रुपए, चालू) और गेलेकी (164 करोड़ रुपए, प्रक्रियाधीन),
- पीएनपी रुद्रसागर - 344 करोड़ रुपए (प्रक्रियाधीन),
- पीएनपी लाइपलिंगोअन - 64 करोड़ रुपए (आरंभ की गई),
- गेलेकी में नया गैस कम्प्रेसर संयंत्र (जीसीपी) - 164 करोड़ रुपए (प्रक्रियाधीन)।

ये उन्नयन कार्य असम राज्य में सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी हाइड्रोकार्बन प्रचालन के प्रति सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

सरकार का ध्यान इस क्षेत्र में संसाधन क्षमता का दोहन करने पर केंद्रित है, जिसमें सुरक्षित, संधारणीय और तकनीकी रूप से सुदृढ़ तरीके से ढके (कैप्ड) इस कूप से जुड़े संसाधन भी शामिल हैं, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पर्यावरणीय संरक्षण और जन कल्याण के साथ आर्थिक अवसर संतुलित रहे।

*****